Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 2039–2045

PARTITION OF INDIA 1947: CHALLENGES AND SOLUTIONS OF REFUGEES IN DELHI AND PUNJAB

भारत विभाजन 1947: दिल्ली और पंजाब में शरणार्थियों की चुनौतियाँ और समाधान

Mubasshir [1], Dilawar Nabi Bhatt [2]

[1] Research Scholar, Department of History, NIMS University Rajasthan, Jaipur, India
[2] Assistant Professor, Department of History, NIMS University Rajasthan, Jaipur, India

Corresponding Author
Mubasshir, mubasshir7772@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.2052

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: The Partition of India in 1947 led to the most traumatic mass migration in history, with over 10 million people displaced across the newly drawn borders of India and Pakistan. This paper examines the processes of migration and resettlement in Delhi and Punjab, two regions affected by Partition. The paper draws comparisons between the different resettlement challenges faced in these regions, highlighting how different socio-economic backgrounds, resource availability and local administrative structures influenced the resettlement experience. The paper also analyses government policies, including the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, and regional initiatives aimed at addressing the specific needs of rural refugees in Punjab and urban refugees in Delhi. The study shows how despite facing challenges such as corruption, land disputes and overcrowding, rehabilitation efforts ultimately contributed to socio-economic improvement of both regions.

Hindi: 1947 में भारत के विभाजन ने इतिहास में सबसे दर्दनाक सामूहिक प्रवासन को जन्म दिया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक लोग भारत और पाकिस्तान की नई खींची गई सीमाओं के पार विस्थापित हो गए। यह शोध पत्र विभाजन से प्रभावित दो क्षेत्रों दिल्ली और पंजाब में प्रवासन और पुनर्वास की प्रक्रियाओं की जांच करता है। शोध पत्र इन क्षेत्रों में होने वाली विभिन्न पुनर्वास चुनौतियों के बीच तुलना करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, संसाधन उपलब्धता और स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं ने पुनर्वास के अनुभव को कैसे प्रभावित किया। यह शोध पत्र सरकारी नीतियों का भी विश्लेषण करता है, जिसमें विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 और क्षेत्रीय पहल शामिल हैं, जिनका उद्देश्य पंजाब में ग्रामीण शरणार्थियों और दिल्ली में शहरी शरणार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है। अध्ययन से पता चलता है कि कैसे भ्रष्टाचार, भूमि विवाद और भीड़भाड़ जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पुनर्वास प्रयासों ने अंततः दोनों क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक सुधार में योगदान दिया।

Keywords: Displaced Persons Act 1954, Mass Migration, Partition of India, 1947, Rehabilitation विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1954, सामूहिक प्रवासन, भारत का विभाजन, 1947, पुनर्वास

1. प्रस्तावना

1947 में भारत का विभाजन इतिहास में सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक सामूहिक प्रवासन में से एक माना जाता हैं, जिसमें 10 मिलियन से अधिक लोग भारत और पाकिस्तान के बीच नई बनी सीमाओं पर विस्थापित होने को मजबूर हो गए। सीमा से अपनी भौगोलिक निकटता के कारण पंजाब और दिल्ली दोनो क्षेत्र इस पलायन के केंद्र थे। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर प्रवासन में नव स्थापित सीमाओं के पार आबादी का एक आंदोलन शामिल था, जिससे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव हुए। (गिलमर्टिन, 1998) पंजाब प्रांत में विभाजन के कारण अनोखी उथल-पुथल हुई, परिवार विभाजित

हो गए, सदियों पुराने रिश्ते टूट गए और व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। राज्य दो भागों में विभाजित हो गया - भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब - जिसके परिणामस्वरूप आबादी में भारी अदला-बदली हुई। हिंदू और सिख पाकिस्तान से पश्चिम की ओर चले गए, जबकि मुस्लिम नवगठित राज्य पाकिस्तान में चले गए।

वहीं राजधानी के रूप में दिल्ली में पश्चिम पंजाब, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत से शरणार्थियों की भारी संख्या में आता देखा गया । कुछ ही महीनों में, इसकी आबादी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई क्योंकि इसमें सैकड़ों-हजारों विस्थापित लोग शामिल हो गए। दिल्ली लगभग रातोंरात बदल गई क्योंकि सीमा के उस पार से शरणार्थी शहर में आ गए, जिससे जनसांख्यिकीय और सामाजिक संरचना में भारी बदलाव आया। (टालबोट एवं सिंह, 2009) अचानक इस जनसांख्यिकीय बदलाव ने दिल्ली के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया, जिससे नई कॉलोनियों व बाजारों की स्थापना हुई और इसके कारण शहर को नया स्वरूप मिल गया । इन क्षेत्रों में पुनर्वास प्रक्रिया का अध्ययन उनके ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय महत्व के कारण महत्वपूर्ण है। पंजाब, विभाजन संघर्ष का गढ़ होने के कारण, और दिल्ली, विस्थापित आबादी के लिए मुख्य शरणस्थली के रूप में सेवा करते हुए, प्रवास के मानवीय आयामों मे अदभुत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पुनर्वास प्रक्रिया में न केवल लाखों विस्थापित लोगों के लिए आश्रय ढूंढना शामिल था बल्कि उन्हें अपने जीवन, समुदायों और पहचान के पुनर्निर्माण में मदद करना भी शामिल था।

इस शोध पत्र का उद्देश्य दिल्ली और पंजाब में शरणार्थियों के सामने आने वाली विभिन्न पुनर्वास चुनौतियों का पता लगाना और उनके बीच तुलना करना है। इसका उद्देश्य इन दोनों क्षेत्रों में विस्थापित लोगो द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों की जांच करना है। शोध पत्र मे यह भी विश्लेषण किया गया हैं कि जनसांख्यिकीय अंतर, संसाधन उपलब्धता, सामुदायिक संरचना और स्थानीय प्रशासन जैसे कारकों ने पुनर्वास प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया और पुनर्वास की सुविधा के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और उपायों का भी अध्ययन किया गया हैं ।

1947 में भारत विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ, जिसमें दिल्ली और पंजाब में सबसे अधिक जनसंख्या परिवर्तन देखा गया। इन दोनों क्षेत्रों में शरणार्थियों की संख्या और उनकी जनसांख्यिकीय संरचना के संदर्भ में विभिन्न अनुभव प्राप्त हुए । विभाजन से पंजाब सबसे अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि यह सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया था। प्रांत में आबादी का लगभग पूर्ण रूप से आदान-प्रदान देखा गया, अनुमानित 5-6 मिलियन हिंदू और सिख पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) से पूर्वी पंजाब (भारत में) की ओर पलायन कर गए, जबकि इतनी ही संख्या में मुस्लिम विपरीत दिशा में चले गए। इलियास चट्ठा सांप्रदायिक हिंसा और स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं के पतन के कारण पंजाब में प्रवासन के असाधारण पैमाने पर प्रकाश डालते है। (चट्ठा, 2011) पंजाब में प्रवासन का पैमाना और गति अस्वाभाविक थी, जो व्यापक सांप्रदायिक हिंसा, भय और स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं के पतन से प्रेरित थी। भारतीय पंजाब में आने वाले शरणार्थी मुख्य रूप से कृषक समुदाय से थे जैसे किसान, व्यापारी और जमींदार, जो अपने पीछे बहुत सी भूमि और संपत्ति छोड़ कर आए थे। उनके आने से क्षेत्र का जनसांख्यिकीय परिदृश्य बदल गया, क्योंकि जो गाँव और कस्बे खाली हो गए थे वो उनके आने से फिर से आबाद हो गए।

जबकि शहरी केंद्र के रूप में राजधानी दिल्ली में प्रवासन से एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ । विभाजन के पश्चात शुरुआती महीनों में शहर में लगभग पांच लाख शरणार्थियों आए, जिनकी संख्या 1950 के दशक की शुरुआत में बढ़कर लगभग 800,000 हो गई। सिंह बताते हैं कि दिल्ली में शरणार्थियों के आने से शहरी क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ और नई बस्तियों का निर्माण हुआ जिसने शहर को नया भौगोलिक आकार दिया। (सिंह, 2024) पंजाब के विपरीत, जहां अधिकांश प्रवासी ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, वहीं दिल्ली में शरणार्थी व्यवसाय वर्ग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मामले में भिन्न थे। इनमें पेशेवर, नौकरशाह, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग शामिल थे जो राजधानी के हलचल भरे शहरी वातावरण में अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। प्रवासित लोगो में मुख्य रूप से हिंदू और सिख थे, जिसमें कई प्रवासी लाहौर, रावलपिंडी और कराची जैसे शहरों से आए थे। शरणार्थियों के आने से दिल्ली के शहरी ढांचे में भारी बदलाव आया, जिससे लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग और किंग्सवे कैंप जैसी नई बस्तियों का निर्माण हुआ।

विभाजन के कारण हुए बड़े पैमाने पर प्रवासन ने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया जिसके लिए तत्काल सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ी । दिल्ली और पंजाब को प्रतिदिन आने वाले लाखों विस्थापित लोगों को राहत और आश्रय प्रदान करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाजपेयी और किदवई ने दावा किया कि शरणार्थी संकट पर सरकार की प्रारंभिक प्रतिक्रिया आपातकालीन राहत और बड़े पैमाने पर प्रवासन को समायोजित करने के लिए शिविरों की स्थापना पर केंद्रित थी। (बाजपेई एवं किदवई, 2012) सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक दिल्ली और पंजाब दोनों में अस्थायी शरणार्थी शिविर स्थापित करना था। इन शिविरों को विस्थापित आबादी को तत्काल आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

दिल्ली में, किंग्सवे कैंप, पुराना किला और लाल किला जैसे स्थानों पर बड़े शिविर स्थापित किए गए थे। सिंह बताते हैं कि कैसे ये शिविर जल्द ही भीड़भाड़ होने की वजह से शरणार्थी अस्थायी परिस्थितियों में रहने लगे । (सिंह, 2024) पंजाब में, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों में शिविर स्थापित किए गए, जहाँ विस्थापित परिवारों को तब तक रखा गया जब तक कि अधिक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती।

सरकार ने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर शिविरों में भोजन, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सहायता और स्वच्छता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राहत कार्यों का समन्वय किया। भारतीय रेड क्रॉस, स्थानीय धर्मार्थ संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सरकारी प्रयासों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राशन और आवश्यक आपूर्ति का वितरण शिविरों में स्थापित राहत समितियों द्वारा किया गया था। हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए चिकित्सा टीमों को तैनात किया गया था, जो खराब रहने की स्थिति के कारण तेजी से फैलती थीं।

प्रारंभिक चरण के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नई सीमा पार प्रवास करने वाले लाखों लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना था। सरकार ने शरणार्थियों को सुरक्षित गंतव्यों तक पहुँचने में मदद करने के लिए विशेष रेलगाड़ियों, काफिलों और कारवां का आयोजन किया। कुछ मामलों में सांप्रदायिक हिंसा से बचाने के लिए सैन्य और पुलिस सुरक्षा प्रदान की । इन प्रयासों के बावजूद, शरणार्थी काफिलों पर अक्सर हमले होते रहे, खासकर पंजाब में, जिससे सुरक्षा प्रबंधन में तत्परता की भावना पैदा हुई।

सरकार ने पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक रणनीति विकसित करते हुए अस्थायी पुनर्वास योजनाएं भी शुरू कीं। दिल्ली में, शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए जल्दबाजी में बनाए गए आश्रयों और खाली इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया। सरकार ने अधिक स्थायी आवास के निर्माण के लिए खाली भूमि को खोजना शुरू कर दिया। पंजाब में, जहां कई शरणार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, उन्हें राज्य के पूर्वी हिस्से में भूमि और कृषि संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए।

विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन ने दिल्ली और पंजाब में लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा कीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने मुआवजा, पुनर्वास और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू कीं। इनमें से, विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 एक ऐतिहासिक उपाय के रूप में सामने आता है, साथ ही कई क्षेत्रीय पहल भी हैं जो विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब में शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई थी । (कॉल, 2015)

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954, एक व्यापक नीति थी जो पाकिस्तान में शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के लिए मुआवजा प्रदान करने और भारत में उनके पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अधिनियम ने शरणार्थियों को पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर मुआवजे का दावा करने की अनुमति दी। मुआवजा मुख्य रूप से जमीन, मकान या दुकानों के रूप में दिया गया था जो पाकिस्तान में पलायन करने वाले मुसलमानों द्वारा खाली छोड़ दिए गए थे। पंजाब में, यह नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कई शरणार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि भूमि की आवश्यकता थी। विशेष रूप से जालंधर और लुधियाना जिलों में भूमि आवंटन योजनाएं लागू की गईं, जहां विस्थापित किसानों के बीच भूमि के बड़े हिस्से वितरित किए गए थे।

दिल्ली में, जहां शहरी आवास की मांग बहुत अधिक थी, अधिनियम ने हिंदू और सिख शरणार्थियों को निकासी संपत्तियों (मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई जो चले गए थे) के वितरण की सुविधा प्रदान की। सरकार ने लाजपत नगर, राजिंदर नगर और पटेल नगर जैसे क्षेत्रों में नई शरणार्थी कॉलोनियों के विकास जैसी आवास योजनाएं भी शुरू कीं। (कौर, 2007) बाजपेयी और किदवई ने कहा कि इन इलाकों में अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक समूहों को समायोजित करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें दावेदारों की पात्रता के आधार पर भूखंड और घर आवंटित किए गए थे। (बाजपेई एवं किदवई, 2012) ऐसे मामलों में जहां संपत्ति आवंटन संभव नहीं था, अधिनियम ने बॉन्ड या नकद अनुदान के रूप में वित्तीय मुआवजा प्रदान किया। इसका उद्देश्य विस्थापित व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने, संपत्ति खरीदने या रोजगार सुरक्षित करने में मदद करना था।

पंजाब सरकार ने विस्थापित परिवारों को कृषि भूमि वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े पैमाने पर भूमि पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए गए, खासकर पूर्वी पंजाब में, जहां खाली की गई भूमि को फिर से आवंटित किया गया। शरणार्थियों को उनके द्वारा छोड़ी गई भूमि के जितनी ही भूमि दिलाने का प्रयास किया गया, हालांकि भूमि की गुणवत्ता और उपलब्धता में शरणार्थियों ने अक्सर तनाव और असंतोष जताया । पंजाब सरकार ने आर्थिक पुनर्वास की आवश्यकता को पहचानते हुए सहकारी कृषि समितियों को बढ़ावा दिया और बीज, उपकरण और उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान की। इन उपायों का उद्देश्य शरणार्थी परिवारों की कृषि उत्पादकता को बहाल करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था।

मुआवजे और पुनर्वास की प्रक्रिया अक्सर भ्रष्टाचार और असमानताओं के कारण प्रभावित हुई । पंजाब में, कुछ शरणार्थियों को अपने पीछे छोड़े गए भूखंडों की तुलना में छोटे या कम उपजाऊ भूखंड मिले। टैलबोट का कहना है कि कई शरणार्थी उन्हें आवंटित भूमि की गुणवत्ता से निराश थे, जो अक्सर विभाजन से पहले उनके पास मौजूद भूमि से कम थी। दिल्ली में, कई लोगों ने विभाजन के वर्षों बाद भी खुद को भीड़भाड़ वाले, अपर्याप्त आवास में पाया। (टालबोट एवं सिंह, 2009) सिंह बताते हैं कि दिल्ली में शरणार्थी कॉलोनियों को जीवंत समुदाय होने के बावजूद, भीड़भाड़ और खराब बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कई निवासी खराब परिस्थितियों में रह रहे थे। (सिंह, 2024)

प्रारंभिक संघर्षों के बावजूद, इन नीतियों ने शरणार्थियों के अंततः सामाजिक-आर्थिक एकीकरण में योगदान दिया। दिल्ली में नए समुदायों का उदय हुआ और पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे ठीक हो गई, शरणार्थियों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इलियास चट्ठा का मानना है, पंजाब में शरणार्थी आबादी के एकीकरण ने कृषि क्षेत्र की बहाली और उसके बाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (चट्ठा, 2011) पुनर्स्थापित आबादी ने दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दिल्ली में शरणार्थी संकट के प्रबंधन के लिए पुनर्वास मंत्रालय गठित किया गया था, जो दिल्ली राज्य शरणार्थी पुनर्वास विभाग के माध्यम से संचालित होता था। इस विभाग ने खाली पड़ी संपत्तियों के आवंटन, आवास निर्माण और वित्तीय मुआवजे का समन्वय किया। पुनर्वास मंत्रालय ने अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से, शरणार्थियों की भारी आमद को समायोजित करने के लिए आवास और शहरी नियोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दिल्ली में पुनर्वास प्रयासों को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (बाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण) जैसी कई अन्य एजेंसियों ने शहरी नियोजन और शरणार्थी कॉलोनियों के विकास में भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने बढ़ती शरणार्थी बस्तियों में संसाधनों और सेवाओं के सुचारु वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया।

पंजाब में, शरणार्थी संकट का प्रबंधन पूर्वी पंजाब शरणार्थी पुनर्वास विभाग द्वारा किया गया था, जो राज्य सरकार के अधीन संचालित होता था। अधिकांश प्रवासन की ग्रामीण प्रकृति को देखते हुए, भूमि वितरण और कृषि पुनर्वास पर ध्यान दिया । बाजपेयी और किदवई इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्वी पंजाब शरणार्थी पुनर्वास विभाग का ध्यान मुख्य रूप से ग्रामीण शरणार्थी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि वितरण पर था। (बाजपेई एवं किदवई, 2012) इसके अतिरिक्त, शरणार्थी किसानों को बीज, उपकरण और वित्तीय सहायता के लिए सहकारी समितियों और कृषि विभागों को सक्रिय किया गया। राज्य सरकार ने विशेष रूप से बड़ी वित्तीय और संसाधन आवंटन योजनाओं के समन्वय में केंद्र सरकार के साथ भी सहयोग किया।

विभाजन के बाद लागू की गई पुनर्वास नीतियों का दिल्ली और पंजाब दोनों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। अहमद के अनुसार, दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में शरणार्थियों के पुनर्वास से शरणार्थी कॉलोनियों का निर्माण हुआ, जिसने इन इलाकों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को फिर से परिभाषित किया। (अहमद, 1999) कौल के अनुसार, इस अवधि के दौरान दिल्ली में शरणार्थियों के आने के कारण तेजी से शहरीकरण हुआ, जिससे आवास और बुनियादी सुविधाओं पर प्रभाव पड़ा। हालाँकि, समय के साथ, ये समुदाय दिल्ली के व्यापक शहरी वातावरण में पूरी तरह से एकीकृत होने लगे, जिससे शहर की विविधता और आर्थिक विकास में योगदान हुआ। (कॉल, 2015)

पंजाब में, पश्चिमी पंजाब से हिंदू और सिख शरणार्थियों के आने से ग्रामीण जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ। संपूर्ण गाँव और कृषि भूमि शरणार्थियों द्वारा फिर से आबाद हो गई, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव आया। दत्ता का कहना है कि शरणार्थियों द्वारा नई कृषि पद्धतियों और परंपराओं की शुरूआत ने पंजाब के कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। (दत्ता, 2013) नए निवासी अपनी कृषि पद्धतियाँ और सामुदायिक परंपराएँ लेकर आए, जो मौजूदा स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ मिश्रित हो गईं। समय के साथ, शरणार्थी ग्रामीण जीवन में एकीकृत हो गए और क्षेत्र की कृषि उत्पादकता में योगदान दिया। उनके आने के कारण सांस्कृतिक एकीकरण और नए निवासियों और मौजूदा आबादी के बीच कभी-कभी तनाव भी पैदा होता था । हालाँकि, विस्थापन के साझा अनुभवों और स्थिरता की सामान्य आवश्यकता ने कई क्षेत्रों में एकता की भावना को बढ़ावा दिया। पारंपरिक त्योहारों, स्थानीय रीति-रिवाजों और सामुदायिक रीति-रिवाजों को नए निवासियों की विविध पृष्ठभूमियों को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया गया, जो ग्रामीण पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक छवि में योगदान करते हैं।

पंजाब में, पुनर्वास नीतियों का कृषि पद्धतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नई कृषि तकनीकों, फसल किस्मों और सिंचाई पद्धतियों की शुरूआत ने क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में योगदान दिया। कृषि गतिविधियों में शरणार्थियों के सफल एकीकरण ने पंजाब को विभाजन के कारण हुए व्यवधानों से आर्थिक रूप से उबरने में मदद की। शरणार्थी किसानों ने इस क्षेत्र को भारत के सबसे अधिक उत्पादक कृषि क्षेत्रों में से एक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ, इन किसानों का आर्थिक योगदान पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक रहा।

दिल्ली में शरणार्थी आबादी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बन गई। राजनीतिक दलों ने शरणार्थी समुदाय की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करने के महत्व को पहचाना, जिससे कुछ नीतियां बनी और वादे किए गए। जमींदार का कहना है कि दिल्ली में शरणार्थियों की राजनीतिक संघटन ने विभाजन के बाद के राजनीतिक विमर्श और चुनावी रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (जमींदार, 2007)

पंजाब में शरणार्थियों के आगमन ने राजनीतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। शरणार्थी एक प्रमुख मतदान समूह बन गए, और उनकी उपस्थिति ने चुनावी परिणामों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया। रॉय इस बात पर जोर देते हैं कि क्षेत्र की सामाजिक-राजनीतिक पहचान को विस्थापित आबादी के आने से नया आकार मिला, जिन्होंने प्रतिनिधित्व और संसाधनों की मांग की। (रॉय, 2012) शरणार्थी अपने अधिकारों की वकालत करने वाले राजनीतिक आंदोलनों में भी शामिल हुए, जिन्होंने विभाजन के बाद पंजाब की व्यापक राजनीतिक गतिशीलता में योगदान दिया।

2. निष्कर्ष

1947 के विभाजन के बाद दिल्ली और पंजाब में पुनर्वास की प्रक्रिया ने दोनों क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्यों को गहराई से प्रभावित किया। पंजाब में मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के शरणार्थियों का पुनर्वास हुआ, जिनके लिए सरकार ने कृषि भूमि और संसाधन उपलब्ध कराए। भूमि वितरण की योजनाएँ शुरू की गईं, जिससे शरणार्थियों को खेती में शामिल किया गया। हालांकि, भूमि की गुणवत्ता और वितरण में आई समस्याओं के कारण कई शरणार्थियों में असंतोष भी देखने को मिला। इसके

बावजूद, शरणार्थियों के कृषि उत्पादकता में योगदान ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दिल्ली में स्थिति भिन्न थी, जहाँ विभाजन के बाद बड़ी संख्या में शहरी शरणार्थी पहुँचे। सरकार ने दिल्ली के शरणार्थियों के लिए आवासीय कॉलोनियाँ, जैसे लाजपत नगर और राजिंदर नगर, विकसित कीं, जिससे शहर की भौगोलिक और सामाजिक संरचना में व्यापक बदलाव आया। हालाँकि इन नई कॉलोनियों ने दिल्ली को एक नया रूप दिया, फिर भी कई शरणार्थी लंबे समय तक भीड़भाड़ और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से जूझते रहे। सरकारी नीतियाँ, विशेष रूप से विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम 1954, ने दोनों क्षेत्रों में पुनर्वास प्रक्रिया को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस अधिनियम ने शरणार्थियों को उनकी खोई हुई संपत्ति के बदले मुआवजा दिलाने और उन्हें नए सिरे से बसाने में मदद की। समग्र रूप से, दिल्ली और पंजाब दोनों में पुनर्वास प्रक्रिया ने न केवल शरणार्थियों को एक नई पहचान और स्थिरता दी, बल्कि इन क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। पुनर्वासित शरणार्थियों ने अपने जीवन को पुनः स्थापित करते हुए क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विभाजन के बाद के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाइ ।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Ahmad, I. (1999). The 1947 Partition of India: A Paradigm for Pathological Politics in India and Pakistan, Asian Affairs, 30(2), 194-205.

Bajpai, K. S., and Kidwai, A. R. (2012). Resettlement of Refugees in India: Government Initiatives and Social Consequences, Journal of Historical Studies, 45(3), 243-268.

Chand, G. (2007). The Resettlement Process in Punjab after the Partition of 1947: Issues and Challenges, Punjab Journal of Social Sciences, 12(1), 65-82.

Chattha, I. (2011). Partition and Locality: Violence, Migration and Development in Gujranwala and Sialkot, 1947-1961, Karachi: Oxford University Press.

Dutta, V. N. (2013). Punjab 1947: A Memoir, New Delhi: Har-Anand Publications.

Gilmartin, D. (1998). Partition, Pakistan and South Asian History: In Search of a Narrative, The Journal of Asian Studies, 57(4), 1068-1095.

Hassan, M. (2001). The Partition Omnibus, New Delhi: Oxford University Press.

Kaul, N. (2015). Resetting Refugees: The Role of the Government in Post Partition India, Indian Historical Review, 42(2), 157-179.

Kaur, R., (2007), Since 1947, Partition Narratives Among Punjabi Migrants of Delhi, Oxford University Press.

Qudaisia, G. (2006). Partition and the Making of the Indian Public: The Hidden History of the Transfer of Power, New Delhi: Sage Publications.

Pandey, G. (2001). Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India, Cambridge: Cambridge University Press.

Roy, K. (2012). Partition of India: The Human Dimension, History and Sociology of South Asia, 6(1), 1-27.

Talbot, I., Singh, G. (2009). Partition of India, Cambridge: Cambridge University Press.

Tan, T.Y., Qudaisia, G. (2000). The Aftermath of Partition in South Asia, London: Routledge.

The Changing Face of Delhi: 1947 to 1957 Punjab Partition. 13 August 2023, www.punjabpartition.com/single-post/the-changing-face-of-delhi-1947-to-1957Accessed 27 August 2024.